1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम0ओ0आर0टी0एण्डएच0), भारत सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के महत्व पर विचार करते हुये 2015 में, हरित राजमार्ग नीति की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिषन () शुरु किया है। एक ओर विकास, रोजगार सृजन और गरीबी में कमी और दूसरी ओर वाहनों के प्रदूषण, वन मोड और पेंड़ों की कटाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की आवष्यकता। ग्रीन कोरिडोर, जलवायू शमन और अनुकूलन दोनों दृष्टिकोंणों से प्रासंगिक, कार्बन उत्सर्जन में स्वैच्छिक कमी के लिये भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये एक समाधान के रुप में देखा जा रहा है। भारत सरकार ने स्थाई समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, सरकारी एजेंसियों और वन विभागों (राज्य स्तर) की भगीदारी के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने की योजना बनाई है। अब तक 650 करोड़ रुपये (लगभग 90 लाख अमेरिकी डालर) के 5000 किमी से अधिक एवेन्यू वृक्षारोपण कार्यों को निष्पादित किया गया है।

2. परियोजना का उद्देष्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिये हरित एवं जलवायु अनुकूल निर्माण विधियों को अपनाकर और उन्हें नेटवर्क के पायलट अनुभागों में लागू करके परिवहन सम्पर्क में सुधार के लिये .... की संस्थागत क्षमता को बढाना है। परियोजना के तीन प्रस्तावित घटक है।

- घटक एक – ग्रीन हाइवे कोरिडोर का सुधार एवं रखरखाव
- घटक दो – संस्थागत क्षमता संवर्धक
- घटक तीन – सड़क सुरक्षा

3. प्रारंभिक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ....द्वारा 8 मे से 4 (चार) उम्मीदवार सड़कों यानि आंध्रप्रदेश में 2 (दो), राजस्थान में 1 (एक), हिमाचल प्रदेश में 1 (एक) के लिये सर्वेक्षणों के आधार तैयार किया गया है। 4 सड़कों के लिये प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, कुल 370 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा, जिसमें लगभग 2835 संरचनायें पूर्ण या आंशिक रुप से, लगभग 6513 घरों और 15547 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित करेगी। यह भी पहचाना गया है कि आर0ओ0डब्ल्यू0 पूरी तरह से बाधाओं से मुक्त नही है और कई जगहों पर लोगों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिये मुख्य रुप से बस्तियों के पास और बाजार स्थानों पर इसका अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया है। आंध्रप्रदेश के परियोजना राज्यों में जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता हो सकती है।

4. विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन के पूरा होने पर, परियोजना प्रभावित लोगो की जनगणना और नमूना सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर एक सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0आईए0) रिपोर्ट और पुनर्वास कार्य योजना (आर0ए0पी0) तैयार

की जा रही है। प्रत्येक सड़क–परियोजना में एस0आई0ए0 किया जाता है ताकि विस्थापन और संभावित नुकसान के परिणाम को निर्धारित किया जा सके, लक्ष्‍ के लिये कमजोर समूहो की पहचान की जा सके, पुर्नवास की लागत का पता लगाया जा सके और कार्यान्वयन के लिये एक पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया जा सके।

5. यह पुनर्वास नीति ढांचा (आर0पी0एफ0) इस पर आधारित है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित एम0ओ0आर0टी0एच0 द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देश दिनांक 28.12.2017ए उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष भूमि खरीद नीति 2015, पंचायतो के प्राविधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996, स्वदेशी लोगों के लिये विश्व बैंक की परिचालन नीति (ओ0पी0–4.10), अनैच्छिक पुनर्वास के लिये विष्व बैंक की परिचालन नीति (ओ0पी0–4.12) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्राविधानों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा, और भूमि के लिये मंआवजे का निर्धारण करते समय सक्षम प्रधिकारी को (आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0) अधिनियम 2013के प्राविधानों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

6. एक इंटाइटलमेंट मैट्रिक्स (ई0एम0) विकसित किया गया है, जो हानियों के प्रकारों और पात्रताओं की संगत, प्रकृति और दायरे को सारांशित करता है। प्रभाव की अवधि और परिणाम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के नुकसान के लिये मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्रदान की गयी है। कमजोर लोगों के लिये अतिरिक्त सहायता, महिलाओं के नाम पर मुआवजे और सहायत के साथ भूमि सम्पत्ति खरीदने वालों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुलक की प्रतिपूर्ति, शारीरिक रुप से विस्थापित लोगों को आवास के लिये नकद सहायता (ई0एम0) में निहित कुछ प्राविधान है।

7. प्रभावित संरचनाओं और अन्य सम्पत्तियों की प्रतिस्थापन राषि की गणना (बी0एस0आर0) दरों पर की जायेगी और जिला स्तरीय समिति/पीआईयू द्वारा अनुमोदित की जायेगी। पी0ए0पी द्वारा उनकी पात्रता, प्रभावित सम्पत्तियों की प्रतिस्थापन लागत और किसी भी अन्य अधिकारों के सम्बनध में रिपोर्ट की गयी किसी भी षिकायत को षिकायत निवारण समिति के माध्यम से सम्बोधित किया जायेगा।

8. प्रत्यक्ष क्रय विधि या भूमि पट्टे, संरचनाओं और अन्य सम्पत्तियों (पेंड, फसल, और अन्य सम्पत्ति, नलकूप, हैंडपम्प) के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के मामले में भूमि की प्रतिस्थापन लागत तय करने के लिये जिला स्तर पर एक प्रतिस्थापन लागत समिति का गठन किया जायेगा। समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर/उपाध्यक्ष कर सकते

है। आयुक्त या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (एस0डी0एम0 पद से नीचे नही), सम्बन्धित पी0आई0यू0 के परियोजना निदेषक–सह कार्यकारी अभियन्ता, जिला कृषि अधिकारी, रेंज अधिकारी (वन विभाग, यदि आवष्यक हो), एक स्वतन्त्र प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता, सम्बन्धित के कार्यकारी अभियंता सम्बन्धित क्षेत्र के जिला, निर्वाचित प्रतिनिधि (एम0एल0ए0) और आ0ए0पी0 कार्यान्वयन एजेंसी के टीम लीडर।

9. एल0ए0 और आर0एवंआर0 पर अधिक से अधिक विवादों को परामर्ष और बातचीत के माध्यम से निपटाने के उद्देष्य से परियोजना प्राधिकरण द्वारा जी0आर0सी0 का गठन किया जायेगा। प्रत्येक पी0आई0यू0 के लिये एक जी0आर0सी0 होगा। जी0आर0सी0 में एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/समाज कल्यान अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्य सामिल होगें जा समूह । जी0आर0सी0 के अन्य सदस्यों में सम्बन्धित परियोजना निदेषक–सह कार्यकारी, एक सेवानिवृत्त पी0डब्ल्यू0डी0 अधि ाकारी (कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे नही)ए आर0आर0ओ0, पी0ए0पी0 के प्रतिनिधि और सम्बन्धित गांव के सरपंच (गांव के निर्वाचित प्रमुख) शामिल होंगे।

10. आर0ए0पी0 और आर0एवंआर0 नीति जैसे दस्तावेजों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया जायेगा जैसा कि परियोजना राज्यों के लिये लागू है और एम0ओ0आर0टी0एच0 और राज्य पी0डब्लयू0डी0 वेबसाइटों के माध्यम से खुलासा किया जायेगा। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दष्तावेजों में शामिल होंगे, इंटाइटलमेंट मैट्रिक्स और आर0ए0पी0 (स्थानीय भाषा में सारांष) और विभिन्न आर0एण्डआर0 लाभें के लिये पात्र पी0ए0एफ0 की सूची। सभी दष्तावेज एम0ओ0आर0टी0एच0 मुख्यालय, राज्य पी0डब्ल्यू0डी0 और एप–परियोजना पीआईयू कार्यालयों में रखे जायेंगे। डब्ल्यू0बी0 की सूचना नीति तक पंहुच के अनुसार सभी सुरक्षा दस्तावेज विष्व बैंक पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। इस आर0पी0एफ0 दस्तावेज का खुलासा एम0ओ0आर0टी0एच0 और विष्व बैंक दोनों द्वारा भी किया जायेगा।

11. परियोजना राजमार्गो से प्रभावित स्वदेषी लोगों के विकास कि लिये परियोजना खण्ड विषिष्ट स्वदेषी जन विकास येाजनाऐं (आई0पी0डी0पी0) इस दष्तावेज में अलग से तैयार की गयी है।

12. जब भी लागू कानूनों या नीतियों में परिवर्तन या संषोधन किये जाते है और कार्यान्वयन के अनुभव और सीखे गये सबक के आधार पर इस पुनर्वास नीति ढांचे को अद्यतन किया जायेगा।

A निजी कृषि, घरेलू और वाणिज्यिक भूमि का नुकसान			
क्रम संख्या	प्रभाव	हकदार इकाई	पात्रता विवरण
1	भूमि की हानि (कृषि, रियासत, वाणिज्यिक या अन्य) गलियारे के भीतर	मालिकाना हक / मालिक / पारंपरिक भूमि अधिकार वाले परिवार / अधिभोगी	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गयी सभी भूमि के लिये मुआवजे / पट्टे की राशि की गणना और भुगतान RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 एवं अनुसूची । के अनुसार किया जायेगा **i. भूमि पर आंशिक प्रभावः** यदि किसी भूमि भूखंड का केवल A हिस्सा प्रभावित होता है, और उसका मालिक चाहता है कि पूरे भूखंड का अधिग्रहण इस आधार पर किया जाये कि भूखंड अलाभकारी हो गया है या भू–अधिग्रहण (धारा 94 और नोट सी के तहत) के कारण अलग हो गया है, तो सक्षम प्राधिकारी भूखंड के शेष भाग के लिये मुआवजा प्रदान कर सकता है या शेष भूमि जोत के वास्तविक मूल्य का 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के रुप में दे सकता है, जिससे मालिक को शेष भूमि भूखंड को बनाए रखने की अनुमति मिलती है, यदि वह सहमत हो। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित सभी भूमि के लिये, या लापता भूमि पार्सलप्लाट / एमओआरटी की सीधी खरीद या अधिग्रहणी एवं एच परिपत्र दिनांक 28.12.2021), पुनर्वास और पुनर्वास सहायता अनुसूची 2013 अधिनियम के आधार पर निम्नानुसार होगी। ii.यदि भूमि अधिग्रहण के परिणमस्वरुप, भूमि का मालिक भूमिहीन हो जाता हो या छोटा किसान की स्थिति में आता है या सीमांत है तो सहायता राशि 06 लाख रु0 होगी। अथवा वार्षिक नीतियां जो कृषि मजदूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिये उपयुक्त सूचीकरण के साथ बीस साल के लिये प्रत्येक प्रभावित भूमि मालिक के लिये प्रति माह दो हजार से कम का भुगतान नही करेगी। iii.प्रत्येक भूमि मालिक को एक बार का पुनरस्थापन भत्ता 60,000 रु0 दिया जायेगा। iv.परियोजना द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतिस्थापन भूमि के लिये किये गये स्टाम्प शुल्क और पुजीकरण शुल्क की वापसी, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रतिस्थापित भूमि खरीदी जानी चाहिये।
Bनिजी संरचनाओं का नुकसान (वाणिज्यिक / आवासीय)			
2	गलियारे के भीतर	शीर्षक धारक / स्वामी	i. RFCTLARRअधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 और सूची । के अनुसार मुआवजा

	संरचना		ii. प्रभावित संरचनाओं से सामग्री के निस्तारण का अधिकार iii. संरचना खाली करने के लिये तरन महीने का अग्रिम नोटिस iv. मवेशी शेड खोने वालों के लिये एकमुश्त 28,000/– की सहायता राशि देय होगी। v. एक कारीगर या स्व–नियोजित या स्वयं की गैर कृषि भूमि के प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिये, जो विस्थापित है और जिसे सथानांतरित करना होगा, को एकमुश्त 28,000/– की सहायता राशि देय होगी। vi. रु0 40,000/– का एकमुश्त निर्वाह अनुदान प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिये जो विस्थापित है और जिन्हें स्थानांन्तरित करने की आावश्यकता है। vii. 60,000/– रु की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिये परिवार, भवन निर्माण सामग्री, सामान एवं मवेशियों के स्थानांन्तरण के लिये स्थानान्तरण/परिवहन के लिये। viii. नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिये निर्धारित बाजार मूल्य पर प्रचलित दरों पर स्टाम्प शुल्क की वापसी। मुआवजे के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर वैकल्पिक मकान/दुकानें खरीद जी जानी चाहिए। ix. खोये हुये घर के लिये, इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित घर प्रदान किया जायेगा या इसके बदले में निर्मित घर के समकक्ष लागत देय होगी। x. आंशिक प्रभाव के मामले में क्षति की मरम्मत को सक्षम करने के लिये संरचना के प्रभावित हिस्से के लिये मुआवजे के पुरस्कार पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुरस्कार का भुगतान किया जाना है, जहां मालिक/अपनी इच्छा के मालिक, संरचना के शेष हिस्से को बनाये रखने के इच्छुक हैं, बशर्ते ऐसी संरचना का निरन्तर उपयोग खतरों के बिना सम्भव है।
3	भीतरी संरचना	किरायेदार/पट्टा धारक	i. पंजीकृत पट्टेदार लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय मुआवजे के विभाजन के हकदार होंगे। ii. परिवहन एवं पुनर्वास हेतु 60,000/– रु0 की एकमुश्त वित्तीय सहायता के रुप में। iii. भवन खाली करने को तान माह का नोटिस।
Cपेड़ों एवं फसलों का नुकसान			
4	गलियारे के भीतर खडे पेंड़ एवं फसलें	मालिक और लाभार्थी (पंजीकृत/अपंजीकृत) किरायेदार, अनुबंध किसान पट्टाधारक	i. अधिनियम की धारा 29(3) के तहत अनुमानित नकद मुआवजे का भुगतान निम्न द्वारा अनुमानित दर से किया जाना है। • लकड़ी के पेड़ों के लिये वन विभाग • फसलों के लिये राज्य कृषि विस्तार विभाग • फल/फूल वाले वृक्षों के लिये उद्यान विभाग

			ii. परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को फलों की कटाई, खडी फसल और पेंड़ों को हटाने के लिये तीन महीने का अग्रिम नोटिस, या ऊपर निर्धारित मुआवजा। पंजीकृत काश्तकार, अनुबंधित किसान और पट्टाधारक और बटाईदार मालिक और लाभार्थियों के बीच समझौते के दस्तावेज के अनुसार पेंड़ों और फसलों के मुआवजे के लिये पात्र होंगे। अपंजीकृत काश्तकार, ठेका कृषक, पट्टाधारक एवं बटाईदार मालिक एवं हितग्राहियों के बीच आपसी समझ के अनुसार पेंड़ों एवं फसलों के मुआवजे के पात्र होंगे।
Dगैर–शीर्षक धारकों को आवासीय / वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान			
5	स्रकारी भूमि के भीतर की संरचनायें	जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार पहचान की गयी संरचनाओं के कब्जेदार (अतिक्रमणकर्ता, स्ट्रक्चर्स)	**घर के नुकसान के लिये** i. संरचना के लिये मूल्यह्यस के बिना पी0डब्ल्यू0डी0 बी0एस0आर0 के आधार पर मुआवजा ii. 28,000 / – रु0 एकमुश्त पुनर्वास भत्ता। iii. 60,000 / – रु0 की स्थानान्तरण / परिवहन सहायता iv. टतिक्रमणकारियों को कब्जे वाली जमीन खाली करने या संरचनाओं के नुकसान के लिये प्रतिसथापन लागत पर नकद सहायता देने के लिये तीन मींने का नोटिस दिया जायेगा। **दुकान के नुकसान के लिये** i. संरचना के लिये मूल्यह्यस के बिना पी0डब्ल्यू0डी0 बी0एस0आर0 के आधार पर मुआवजा ii. 40,000 / – रु0 एकमुश्त निर्वाह अनुदान। iii. 28,000 / – रु0 एकमुश्त पुनर्वास अनुदान। iv. 60,000 / – रु0 स्थानांन्तरण / परिवहन सहायता। v. अतिक्रमणकारियों को कब्जे वाली जमीन खाली करने के लिये तीन महीने का नोटिस दिया जायेगा या संरचनाओं के नुकसान के लिये प्रतिस्थापन लागत पर नकद सहायता दर जायेगी। vi. प्रभावित सामग्री को उबारने का अधिकार।
Fकमजोर समूह को अतिरिक्त सहायता			
6	कोरिडोर के भीतर प्रभावित होने वाले परिवार	कमजोर प्रभावित परिवार	i. 60,000 / – रु0 का एकमुश्त पुनर्वास भत्ता। ii. कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण। इस सहायता में प्रशिक्षण की लागत और यात्रा / वाहन भत्ता और भेजन के लिये वित्तीय सहायता सामिल है।

			iii. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को विस्थापित करने हेतु 60,000/– रु0 अतिरिक्त निर्वाह अनुदान। iv. विस्थापित कमजोर परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ा जायेगा, यदि वे पात्र पाए जाने है और आज तक योजना का लाभ नही उठा पाये है।
Gसामुदायिक अवसंरचना/सामान्य सम्पत्ति संसाधनों की हानि			
7	कोरिडोर के भीतर की संरचानाऐं और अन्य संसाधन जैसे भूमि, पानी तथा संरचनाओं तक पंहुच	प्रभावित समुदाय और समूह	स्मंदायिक संरचना और सामान्य संम्पत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण, समंदाय के परामर्श से किया जायेगा।
Hनिर्माण के दौरान अस्थाई प्रभाव			
8	निर्माण के दौरान अस्थाई रुप से प्रभावित भूमि और सम्पत्तियां	ज्मीन और सम्पत्ति के मालिक	i. परिवर्तन के दौरान असथाई प्रभाव के लिये मुआवजा। भारी मशीनरी और संयंन्त्र स्थल की आवाजाही के कारण सामान्य यातायात का मोड, भूमि/सम्पत्ति (फसल, पेंड़, संरचना, आदि) के आसन्न पार्सल को नुकसान। ii. निर्माण या निर्माण संयंन्त्र की स्थापना के दौरान मशीनरी की आवाजाही के कारण संरचना या भूमि पर किसी भी प्रभाव के मुआवजे की लागत ठेकेदार को वहन करनी होगी। iii. आर0ओ0डब्ल्यू के बाहर भूमि का सभी अस्थाई उपयोग लिखित अनुमोदन/पूर्वानुमोदन भू–स्वामी और ठेकेदार के आधार पर किया जायेगा।

కార్యనిర్వాహక సారాంశం

1. ఆర్థిక వృద్ధిలో రహదారి నెట్‌వర్క్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుని, 2015 సెప్టెంబర్‌లో 'గ్రీన్ హైవేస్ పాలసీ' ప్రకటించిన నేపథ్యంలో రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారి మంత్రిత్వ శాఖ (MoRT & H), భారత ప్రభుత్వం (GoI) జాతీయ గ్రీన్ హైవేస్ మిషన్ (NGHM) ను ప్రారంభించింది. ఉపాధి కల్పన మరియు ఒక వైపు **పేదరికాన్ని తగ్గించడం కొరకు** మరియు వాహన కాలుష్యం, **అడవులను నరికి పట్టణీకరణ చేసి పట్టణ ప్రాంతాలుగా మార్చడం** మరియు మరోవైపు చెట్లను నరికివేయడం వంటి ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించడానికి, కార్బన్ ఉద్గారాలను స్వచ్ఛందంగా తగ్గించడం కోసం భారతదేశం యొక్క **సంకల్పాన్ని** నెరవేర్చడానికి వాతావరణ **వైపరీత్యాల నుండి** ఉపశమనం మరియు అనుసరణ దృక్పథం రెండింటి **విజయవంతంగా అమలు జరుపుటకు** గ్రీన్ కారిడార్లు ఒక పరిష్కారంగా చూడబడుతున్నాయి . **ఈ జి.ఒ.ఐ. ప్రణాళికలు స్థానిక సంఘాలు,** రైతులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రైవేటు రంగం, ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు అటవీ శాఖలు (రాష్ట్ర స్థాయి) భాగస్వామ్యంతో **జాతీయ రహదారుల పై** తోటల పెంపకాన్ని చేపట్టాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటివరకు, 650 కోట్ల రూపాయల (సుమారు 90 మిలియన్ డాలర్లు) విలువైన 5,000 కిలోమీటర్ల **మేర జాతీయ రహదారిపై మొక్కలు నాటించి అవెన్యూ ప్లాంటేషన్** పనులు అమలు చేయబడ్డాయి.

2. నేషనల్ హైవే నెట్‌వర్క్ కోసం ఆకుపచ్చ మరియు **వాతావరణంలో అధిక వేడిమి ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితులను తగ్గించే** నిర్మాణ పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా మరియు వాటిని నెట్‌వర్క్ యొక్క **ప్రయోగ విభాగాలు వాటిని పరీక్షించి అమలు** చేయడం ద్వారా రవాణా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడంలో MoRT & H యొక్క సంస్థాగత సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం . ప్రాజెక్ట్ యొక్క మూడు ప్రతిపాదిత **అంశాలు** ఉన్నాయి:

- **అంశం** ఎ: గ్రీన్ హైవే కారిడార్ మెరుగుదల మరియు నిర్వహణ
- **అంశం** బి: సంస్థాగత/**వ్యవస్థాగత** సామర్థ్యం పెంపు
- **అంశం** సి: రహదారి భద్రత

3. ప్రారంభ సామాజిక ప్రభావ అంచనా 4 (నాలుగు) దరఖాస్తు చేయబడిన **రోడ్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2 (రెండు), రాజస్థాన్ లో 1 (ఒకటి) మరియు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో 1 (ఒకటి) ను MoRTH ద్వారా** సదరు రహదారి **అభివృద్ధి పనులు చేశారు మరియు 4 రోడ్ల కోసం చేసిన సర్వేల ప్రకారం 8 రహదారులలో, మరియు బ్యాలెన్స్ 4 రోడ్లకు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాథమిక అంచనాలలో, మొత్తం 370 హెక్టార్ల ప్రైవేట్ భూమి 2835 నిర్మాణాలు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ప్రభావితం అవుతున్నాయి, సుమారు 6513 గృహాలు మరియు 15547 ప్రాజెక్ట్‌లపై ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్.ఒ.డబ్ల్యుకు కు రుణభారం నుండి పూర్తిగా విముక్తి కాలేదు మరియు అనేక ప్రదేశాలలో వివిధ ప్రయోజనాల ప్రధాన్యంగా సమీపంలో నివాసాలు మరియు మార్కెట్ ప్రదేశాల్లో ప్రజలు, ఆక్రమిస్తున్న రోడ్ల ప్రాంతాలు ప్రతికూల పరిస్థితులను కలిగిస్తున్నాయి. రోడ్ల అప్‌గ్రేడింగ్ చేయవల్సిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గిరిజన ప్రాబల్య ప్రాంతాల్లో అండర్ టేకింగ్ నిర్వహణ బాధ్యతలను చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.**

4. వివరణాత్మక ఇంజనీరింగ్ డిజైన్లను పూర్తి చేసిన తరువాత, ప్రభావిత జనాభా యొక్క జనాభా గణన మరియు సామాజిక-ఆర్థిక సర్వే నమూనా ఆధారంగా సామాజిక ప్రభావ అంచనా (SIA) నివేదిక మరియు పునరావాసం కార్యాచరణ ప్రణాళిక (RAP) తయారు చేయబడుతున్నాయి. ప్రతి రహదారి ప్రాజెక్టులో SIA **ఈ పనులు** చేపట్టబడుతుంది, తద్వారా కాబోయే నష్టాల పరిమాణం నిర్ణయించడం, లక్ష్యానికి హాని కలిగించే **కారకాలను** గుర్తించడం, పునరావాసం యొక్క ఖర్చులను నిర్ధారించడం మరియు పునరావాసం అమలు కోసం మరియు పునరావాస కార్యక్రమాన్ని సిద్ధం చేయడం **వంటి పనులు విజయవంతంగా నిర్వహించబడే అవకాశాలున్నాయి**

5. ఈ పునరావాస విధాన ముసాయిదా (RPF) వీటిపై ఆధారపడి పనిచేయును: భూసేకరణ, పునరావాసం మరియు పునరావాసం చట్టం, 2013 (RFCTLARR) లో సరసమైన పరిహారం మరియు పారదర్శక**ంగా నష్టపరిహారం పొందే** హక్కు; జాతీయ రహదారి చట్టం 1956; NH చట్టం 1956 ప్రకారం LA కి సంబంధించి MORTH జారీ చేసిన సమగ్ర మార్గదర్శకాలు 28 డిసెంబర్ 2017 నాటివి; ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రత్యక్ష భూ కొనుగోలు విధానం, 2015; పంచాయతీల కేటాయింపులు (షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలకు పొడిగింపు) చట్టం, 1996; స్వదేశీ ప్రజల కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు కార్యాచరణ విధానం (OP-4.10), అసంకల్పిత పునరావాసం కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు కార్యాచరణ విధానం (OP-4.12). జాతీయ రహదారి చట్టం 1956 లోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడం, మరియు భూమికి పరిహారాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు, సమర్థ అధికారం RFCTLARR చట్టం, 2013 లోని నిబంధనల ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయడం.

6. ఒక అర్హత మ్యాట్రిక్స్ (EM) ఈ దిగువ పేర్కొనబడిన అభివృద్ధి పనులను చేయుటకు ఏర్పాటు చేయబడింది, ఇది నష్టాల రకాలను మరియు సంబంధిత స్వభావం మరియు అర్హతల పరిధిని సంగ్రహిస్తుంది. **కాలపరిమితి** మరియు ప్రభావం యొక్క పరిమాణం ఆధారంగా వివిధ వర్గాల నష్టాలకు పరిహారం మరియు పునరావాస సహాయం అందించబడింది. **సదరు ప్రాజెక్ట్ పనుల వలన హాని కలిగేవారికి** అదనపు సహాయం, స్టాంప్ డ్యూటీ రీయింబర్స్‌మెంట్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు భూమి / ఆస్తిని కొనుగోలు **చేయుటకు** మహిళలకు వారికి పరిహారం **చెల్లించడం** మరియు **గుడిసెలలో నివసించే నిర్వాసితులకు** గృహనిర్మాణానికి నగదు సహాయం EM లో ఉన్న కొన్ని నిబంధనలు.

7. నిర్మాణాలు మరియు ఇతర ఆస్తుల భర్తీ మొత్తం బి.ఎస్.ఆర్. రేట్లపై పని **చేయవలెను** మరియు జిల్లా స్థాయి కమిటీ / పి.ఐ.యు. **దానిని** ఆమోదించ**వలెను**. P.A.P. లు అర్హత, ప్రభావిత ఆస్తుల ఖర్చు మరియు ఇతర అర్హతలకు సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యాదులను **చేయవలసి ఉంటే వాటిని** గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కమిటీ ద్వారా పరిష్కరించాలి.

8. ప్రత్యక్ష కొనుగోలు పద్ధతి లేదా భూమి లీజు ద్వారా నిర్మాణాలు మరియు ఇతర ఆస్తులు (చెట్లు, పంటలు మరియు ఇతర ఆస్తులు, ట్యూబ్ బావి, హ్యాండ్ పంప్ మొదలైనవి) స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల విషయంలో **సదరు భూములకు తగు మూల్యం** భర్తీ చేయడానికి జిల్లా స్థాయిలో **పునరావాస ధరని నిర్ణయించే** కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ కమిటీకి జిల్లా కలెక్టర్ / **డిప్యూటీ** కమిషనర్ లేదా **వారు** నియమించబడిన ప్రతినిధి (ఎస్.డి.ఎమ్ ర్యాంకు

కంటే తక్కువ కాదు), సంబంధిత పి.ఐ.యు యొక్క ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్-కమ్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి, రేంజ్ ఆఫీసర్ (అవసరమైతే అటవీ శాఖ), స్వతంత్ర **సర్టిఫైడ్** వాల్యుయర్, సంబంధిత జిల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, సంబంధిత ప్రాంతానికి ఎన్నికైన ప్రతినిధి (ఎమ్మెల్యే) మరియు ఆర్.**ఎ.పి** అమలు సంస్థ టీమ్ లీడర్ ఈ కార్య నిర్వహణ బాధ్యతలకు అధ్యక్షత వహించవచ్చు.

9. సంప్రదింపులు మరియు చర్చల ద్వారా LA మరియు R&R పై వీలైనన్ని వివాదాలను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ GRC ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రతి పి.ఐ.యు. కు ఒక జి.ఆర్.సి. ఉంటుంది. గ్రూప్ I ఆఫీసర్ ర్యాంకు **కంటే తక్కువ స్థాయి కాని,** రిటైర్డ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ / సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలోని ఆరుగురు సభ్యులను జిఆర్సి కలిగి ఉంటుంది. జి ఆర్‌సిలోని ఇతర సభ్యులలో సంబంధిత ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్-కమ్-ఎగ్జిక్యూటివ్, రిటైర్డ్ పిడబ్ల్యుడి ఆఫీసర్ (ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ర్యాంకు కంటే తక్కువ కాదు), ఆర్.ఆర్.ఓ., పి.ఎ.పి. ల ప్రతినిధి మరియు సంబంధిత గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్ (గ్రామానికి ఎన్నికైన హెడ్) ఉన్నారు.

10. RAP మరియు R&R పాలసీ ప్రాజెక్ట్ పత్రాలు రాష్ట్రాలకు వర్తించే విధంగా **స్థానిక** భాషలలో **అనువదింపవలెను** మరియు MORTH మరియు స్టేట్ పిడబ్ల్యుడి వెబ్‌సైట్ల ద్వారా **సదరు సమాచారాన్ని పొందుపరచవలెను**. పబ్లిక్ డొమైన్ లో లభించే పత్రాలలో ఇవి **ఉండాలి**: అర్హత మ్యాట్రిక్స్ మరియు RAP (స్థానిక భాషలో సారాంశం) మరియు వివిధ R&R ప్రయోజనాల కోసం **అర్హతగల** PAF ల జాబితా. అన్ని పత్రాలు MORTH HQ, State PWD మరియు ఉప-ప్రాజెక్ట్ PIU ల కార్యాలయాల వివరాలు **ఉంచవలెను**. WB యొక్క సమాచార **పంపిణీ నిబంధనల** ప్రకారం అన్ని భద్రతా పత్రాలు ప్రపంచ బ్యాంక్ పోర్టల్ వద్ద కూడా అందుబాటులో **ఉంచవలెను**. ఈ RPF **పత్రాలను** MoRT & H మరియు ప్రపంచ బ్యాంక్ రెండింటి**కి** వెల్లడించాలి.

11. ప్రాజెక్ట్ నందలి అంశా**లను** ప్రాజెక్ట్ రహదారుల ద్వారా ప్రభావితం **కాబడిన నిర్వాసిత** దేశీయ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం విస్తరించిన నిర్దిష్ట **స్వదేశీ ప్రజల** డెవలప్మెంట్ ప్లాన్స్ (IPDP) **డాక్యుమెంట్** పత్రం**ను** ఈ డాక్యుమెంట్ కు ప్రత్యేకంగా విడిగా తయారు **చేయవలెను**.

12. ఈ పునరావాస విధాన ముసాయిదా లో వర్తించే చట్టాలు మరియు **భవిష్యత్తులో** విధానాల మార్పులు లేదా సవరణలు చేసినప్పుడు మరియు ~~ఈ~~ **ప్రాజెక్టుల** అమలు **కాలంలో నేర్చుకున్న** అనుభవ పాఠాల ఆధారంగా నవీనీకరించవలెను.

టేబుల్ 4: మ్యాట్రిక్స్ యోగ్యత

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
ఎ . ప్రైవేట్ అగ్రికల్చరల్, నివాస స్థలం & కమర్షియల్ ల్యాండ్‌ల యొక్క నష్టం			
1	భూమి నష్టం (వ్యవసాయ, ఇంటి స్థలం, వాణిజ్య లేదా ఇతర) **లేదా** (COI) కారిడార్ ఆఫ్ **ఇంపాక్ట్ పరిధిలో సంబంధిం-చినవి.**	**హక్కుదారుడు/యజమాని/ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో హక్కులు గల కుటుంబాలు /** ఆక్రమణదారు**లు**	NH చట్టం క్రింద పొంది**యున్న మొత్తం భూమి** ; పరిహారం / లీజు మొత్తాన్ని 26 నుండి 30 సెక్షన్లు మరియు RFCTLARR చట్టం 2013 యొక్క షెడ్యూల్ I ప్రకారం లెక్కించాలి మరియు చెల్లించాలి . i. **భూమిపై పాక్షిక ప్రభావం**: ఒకవేళ ఏదైనా భూమి ప్లాట్‌లో కొంత భాగం మాత్రమే ప్రభావితమైతే, మరియు **ప్లాట్లకి** ఆర్థికంగా **నష్టం వాటిల్లినమా** లేదా LA (సెక్షన్ 94 మరియు నోట్ సి కింద) ప్రకారం భూసేకరణలో విడదీయబడిందనే కారణంతో మొత్తం ప్లాట్ విలువ తగ్గించబడినట్లు అయిందని, దానికై యజమాని నష్టపరిహారం పొందాలని దాని యజమాని కో**రినట్లయితే**, **తగు అర్హత కలిగిన అథారిటీ,** ప్లాట్ యొక్క మిగిలిన భాగానికి పరిహారాన్ని ఇవ్వగలదు లేదా మిగిలిన భూమిని కలిగి ఉన్న 25% వాస్తవ విలువను అదనపు పరిహారంగా ఇవ్వగలదు, యజమాని అంగీకరిస్తే మిగిలిన భూమి ప్లాట్లు నిలుపుకోవటానికి అనుమతిస్తుంది. NH చట్టం క్రింద పొంది**యున్న మొత్తం భూమి**; లేదా **మిగిలిన భూ భాగముల** / ప్లాట్లు (MoRT & H **సర్క్యులర్** తేదీ 28 డిసెంబర్, 2017), పునరావాసం మరియు **పునరావ్రశయ** సహాయం **చట్టం ప్రకారం** ఈ క్రింది విధంగా ఉండాలి (చట్టం 2013 యొక్క షెడ్యూల్ II): ii. భూసేకరణ ఫలితంగా, భూమి యజమాని భూమిలేనివాడు**గా** లేదా "చిన్న" లేదా "ఉపాంత" సన్నకారు రైతు యొక్క స్థితికి **అతని స్థాయి** తగ్గించబడితే **అట్టి రైతుకి**,

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
			సహాయం మొత్తం రూ. 6 లక్షలు లేదా వ్యవసాయ కూలీల కోసం వినియోగదారుల ధరల సూచికకు తగిన సూచికతో ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రతి బాధిత భూ యజమానికి నెలకు రెండు వేల రూపాయల కన్నా తక్కువ చెల్లించాల్సిన యాన్యుటీ పాలసీలు **అమలుచేయవలెను**. iii. ప్రతి భూమి యజమానికి ఒక **సారి మాత్రమే** "పునరావాసం భత్యం" రూ. 60,000/- చెల్లించాలి. iv. ప్రాజెక్ట్ ద్వారా చెల్లించాల్సిన భర్తీ భూమికి స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల వాపసు; ప్రాజెక్ట్ బాధిత వ్యక్తులకు పరిహారం చెల్లించిన తేదీ నుండి ఒక సంవత్సరంలోపు భర్తీ భూమిని కొనుగోలు చేయాలి
B. ప్రైవేట్ స్ట్రక్చర్స్ నష్టం (రెసిడెన్షియల్ / కమర్షియల్)			
2	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్** యొక్క **అంతర్గత** నిర్మాణం (CoI) కి **సంబంధించినవి**	**హక్కుదారుడు**/ యజమాని	i. 26 నుండి 30 సెక్షన్లు మరియు RFCTLARR చట్టం 2013 యొక్క షెడ్యూల్ I తో **అనుగుణంగా** పరిహారం ii. ప్రభావిత నిర్మాణాల నుండి **మెటీరియల్స్‌ను రీసైక్లింగ్ చేసే** హక్కు iii. నిర్మాణాన్ని ఖాళీ చేయడానికి మూడు నెలల ముందస్తు నోటీసు **ఇచ్చే హక్కు.** iv. పశువుల షెడ్‌ను కోల్పోయేవారికి, **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించబడే నష్టపరిహార సహాయం** రూ. 2 8 , 000 / - **చెల్లించగలదు** v. ఒక శిల్పకారుడు లేదా స్వయం ఉపాధి లేదా వ్యవసాయేతర భూమి యొక్క ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి పునరావాసం **పొందుటకు ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించబడే నష్టపరిహార సహాయం** రూ. 28,000/-

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
			చెల్లించగలదు; మరియు vi. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే జీవనోపాధి** గ్రాంట్ రూ. 40 ,000/- ప్రతి **నిర్వాసిత కుటుంబానికి తిరిగి పునరావాసం కల్పించుకొనుట కొరకు ఇవ్వగలదు.** vii. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే** ఆర్థిక సహాయం రూ. 6 0,000/- **క్రొత్తగా మరియొక నివాస ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన** కుటుంబానికి కుటుంబం, నిర్మాణ సామాగ్రి, వస్తువులు మరియు **పశుసంపదలను** బదిలీ కోసం రవాణా / రవాణా ఖర్చుల **కొరకు సదరు ధన సహాయం చేయగలదు.** viii. నిర్ణయించిన విధంగా మార్కెట్ విలువపై ప్రస్తుత రేట్ల వద్ద కొత్త ప్రత్యామ్నాయ గృహాలు / దుకాణాలను కొనుగోలు చేయడానికి స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీ**లు** వాపసు **చేయవలెను**. పరిహారం చెల్లించిన తేదీ నుండి ఒక సంవత్సరంలోపు ప్రత్యామ్నాయ గృహాలు / దుకాణాలను కొనుగోలు చేయాలి ix. కోల్పోయిన ఇల్లు కోసం, ఇందిరా ఆవాస్ యోజన స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం నిర్మించిన ఇల్లు అందించబడుతుంది లేదా బదులుగా నిర్మించిన ఇంటి **కి** సమానమైన ధర చెల్లించబడుతుంది. x. పాక్షిక ప్రభావం **వాటిల్లిన** విషయంలో, నష్టం మరమ్మత్తును ప్రారంభించడానికి నిర్మాణం యొక్క ప్రభావిత భాగానికి పరిహార అవార్డుపై 25% అదనపు అవార్డు చెల్లించాలి, ఇక్కడ యజమాని / ఆక్రమణదారుడు, అతని / ఆమె స్వంత సంకల్పం **తో** నిర్మాణం యొక్క మిగిలిన భాగాన్ని నిలుపుకోవటానికి ఆసక్తి కలిగి **ఉంటే** అటువంటి నిర్మాణం **ను ఏ** ప్రమాదాలు లేకుండా **ఉపయోగించుకొనవచ్చు.**
3	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్** యొక్క	అద్దెదారులు /	i. వర్తించే స్థానిక చట్టాల ప్రకారం నిర్మాణ

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
	అంతర్గత నిర్మాణం (CoI) కి **సంబంధించినవి**	లీజు హక్కు **దారులు**	యజమానికి చెల్లించాల్సిన పరిహారం చెల్లించాల్సిన సమయంలో రిజిస్టర్డ్ అద్దెదారుల**ను** నియమించి వారి సమక్షంలో చెల్లించే విధంగా అర్హత ఉంటుంది ii. ఒక సారి **మాత్రమే చెల్లించే** ఆర్థిక సహాయం రూ. 60,000/- రవాణా మరియు **పునరావాసం కొరకు** సహాయంగా **చెల్లించబడును**. iii. నిర్మాణాలను ఖాళీ **చేయించడానికి మూడు నెలల ముందుగా** నోటీసు **ఇచ్చే** హక్కు.
C. చెట్లు మరియు పంటల నష్టం			
4	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ పరిధిలో ప్రభావితమయ్యే చెట్లు, పంట లు** (CoI) కి **సంబంధించినవి**	యజమానులు మరియు లబ్ధిదారులు (రిజిస్టర్డ్ / **అన్-రిజిస్టర్డ్** అద్దెదారులు, కాంట్రాక్ట్ సాగుదారులు, లీజుదారులు & వాటాదారులు)	i. చట్టం యొక్క సెక్షన్ 29 (3) ప్రకారం అంచనా వేసిన పరిహారం **ఈ క్రింది** అధికార సంస్థల అంచనా వేసిన రేటుకు చెల్లించాలి: • కలప చెట్ల కోసం అటవీ శాఖ • పంటల కోసం రాష్ట్ర వ్యవసాయ విస్తరణ విభాగం • పండ్ల / పుష్పాలను కలిగి ఉన్న చెట్ల కోసం హార్టికల్చర్ విభాగం. ii. మూడు నెలల ముందుగానే బాధిత వ్యక్తులకు **ముందస్తు నోటీసు జారీ చేసి పళ్లు** పంటలు మరియు చెట్లు **ఫలాలను దిగుమతి చేసు కోవలసినది సూచనలు ఇవ్వడం లేదా వాటి వెలకు తగిన పరిహారాన్ని ఇవ్వవలెను**. రిజిస్టర్డ్ అద్దెదారులు, కాంట్రాక్ట్ సాగుదారులు & లీజుదారులు మరియు వాటాదారులు యజమాని మరియు లబ్ధిదారుల మధ్య ఒప్పంద పత్రం ప్రకారం చెట్లు మరియు పంటలకు పరిహారం పొందటానికి అర్హులు. **అన్ రిజిస్టర్డు** అద్దెదారులు, కాంట్రాక్ట్ సాగుదారులు, లీజుదారులు మరియు వాటాదారులు చెట్లు మరియు పంటలకు పరిహారం పొందటానికి యజమాని మరియు లబ్ధిదారుల మధ్య **కుదుర్చుకున్న** పరస్పర

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
			ఒప్పంద ప్రకారం అర్హులు**కాగలరు**.
D. సరైన టైటిల్ లేని నివాస / వాణిజ్య నిర్మాణాల వారికి/ఆక్రమణదారులకు నష్ట పరిహారం			
5	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ పరిధిలో ప్రభావితమయ్యే నిర్మాణాలు** (CoI) లేదా ప్రభుత్వ భూమి కి **సంబంధించినవి**	ప్రాజెక్ట్ సెన్సస్ సర్వే ప్రకారం గుర్తించబడిన నిర్మాణాల **యజమానులు** నిర్మాణాలు లేదా ఆక్రమణదారులు (**ఆక్రమణదారులు**, **గుడిసెలను వేసుకొని నివాసముండే వారు**)	**ఇంటి నష్టపరిహారం కొరకు** i. నిర్మాణం **యొక్క నష్టపరిహారం** తరుగుదల లేకుండా పి.డబ్ల్యు.డి. బి.ఎస్.ఆర్. పరిహారం **ఇవ్వవలెను** ii. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే** పునరావాసం భత్యం రూ. 28,000 / - iii. **నూతన నివాసమునకు లేక ప్రాతంనకు మారుటకు** / రవాణా **కొరకు** సహాయం రూ. 60 , 000 / - iv. ఆక్రమిత భూమిని ఖాళీ చేయటానికి లేదా నిర్మాణాల నష్టానికి **తగు** భర్తీ ఖర్చుతో నగదు సహాయం ఇవ్వటానికి ఆక్రమణదారులు మూడు నెలల ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాలి. v. ప్రభావిత **సామాగ్రి/**పదార్థాలను రక్షించే హక్కు **షాపుల నష్టపరిహారం కొరకు** i. నిర్మాణం **యొక్క నష్టపరిహారం** తరుగుదల లేకుండా పి.డబ్ల్యు.డి. బి.ఎస్.ఆర్. పరిహారం **ఇవ్వవలెను** ii. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే జీవనాధారం కొరకు** గ్రాంట్ రూ. 40,000 / - iii. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే పునరావాసం కొరకు** మంజూరు **చేయబడే సహాయం** రూ. 28,000 / - iv. **నూతన నివాసమునకు లేక ప్రాతంనకు మారుటకు** / రవాణా **కొరకు** సహాయం రూ. 60,000 / - v. ఆక్రమిత భూమిని ఖాళీ చేయటానికి లేదా నిర్మాణాల నష్టానికి **తగు** భర్తీ ఖర్చుతో నగదు

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
			సహాయం ఇవ్వటానికి ఆక్రమణదారులు మూడు నెలల ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాలి. vi. ప్రభావిత **సామాగ్రి/**పదార్థాలను రక్షించే హక్కు
ఎఫ్. దుర్బల సమూహానికి / **హాని లేదా ఎక్కువ నష్టం కలగడాని అవకాశం ఉన్న సమూహాలవారికి** అదనపు సహాయం కొరకు			
6	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ పరిధిలో ప్రభావితమయ్యే కుటుంబాల కొరకు** (CoI)	**హాని లేదా ఎక్కువ నష్టం కల గడాని అవకాశం ఉన్న** ప్రభావిత కుటుంబాల**వారికి**	i. **ఒకసారి మాత్రమే చెల్లించే** పునరావాసం భత్యం రూ. 60,000 / - ii. నైపుణ్య అభివృద్ధికి శిక్షణ. ఈ సహాయంలో శిక్షణ ఖర్చు మరియు ప్రయాణ / రవాణా మరియు ఆహారం కోసం ఆర్థిక సహాయం **చేయవలెను**. iii. షెడ్యూల్డ్ కులం మరియు షెడ్యూల్డ్ **తెగలకు** చెందిన **నిర్వాసిత** కుటుంబాలకు అదనపు జీవనాధార గ్రాంట్ రూ. 60,000 / - iv. **నిర్వాసితులైన** కుటుంబాల **వారు అర్హత ఉండి** ఈ రోజు వరకు **ఎటువంటి** పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందలేకపోతే **వారిని** ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలతో అనుసంధానించి **వారికి తగు సంక్షేమ పథకాలు అందేవిధంగా సహాయం చేయవలెను**.
జి . కమ్యూనిటీ మౌలిక సదుపాయాలు / **ఉమ్మడి** ఆస్తి వనరుల నష్టం			
7	**కారిడార్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ పరిధిలో వచ్చిన** నిర్మాణాలు & ఇతర వనరులు (ఉదా. భూమి, నీరు, నిర్మాణాలకు ప్రాప్యత మొదలైనవి) (CoI)	ప్రభావిత సంఘాలు మరియు సమూహాలు	**సహాయం అందించవలసిన ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజల కొరకు నిర్మాణాలు** మరియు **ఉమ్మడి** ఆస్తి వనరుల పునర్నిర్మాణం **కొరకు అక్కడ నివసించే ప్రజలనందరినీ** సంప్రదించి **తగిన విధంగా సహాయం చేయవలెను.**
హెచ్ . నిర్మాణ సమయంలో తాత్కాలిక ప్రభావం			
8	నిర్మాణ సమయంలో **తాత్కాలికంగా ప్రభావితమ-య్యే** భూమి మరియు ఆస్తుల **కొరకు**	భూమి మరియు ఆస్తుల యజమానులు **కొరకు**	i. **పని** సమయంలో తాత్కాలిక ప్రభావానికి **గురైన వాటికి** పరిహారం**గా** ఉదా:సాధారణ**ంగా ఏర్పడే** ట్రాఫిక్ యొక్క మళ్లింపు, భారీ యంత్రాలు యొక్క కదలిక కారణంగా మొక్కల ప్రదేశం,

క్ర.సం.	ప్రభావం	అర్హతగల యూనిట్	అర్హత వివరాలు
			(పంటలు, చెట్లు, నిర్మాణాలు మొదలై) **వాటి కొరకు తగు నష్టపరిహారం**. ii. నిర్మాణ సమయంలో యంత్రాల కదలిక కారణంగా నిర్మాణం లేదా భూమిపై ఏదైనా ప్రభావం **ఏర్పడితే దాని** యొక్క **నష్ట** పరిహారం ఖర్చును కాంట్రాక్టర్ భరించాలి. iii. ROW వెలుపల భూమి యొక్క తాత్కాలిక **వినియోగం కొరకు ముందస్తుగా** వ్రాతపూర్వక ఆమోదం / అనుమతిని భూయజమాని **మరియు** కాంట్రాక్టర్ **ద్వారా పొంది దాని** ఆధారంగా **వినియోగించుకోవాలి.**

గమనిక: అన్ని వ్యయములు మరియు సవరించిన ధరలు వ్యవసాయ కార్మికుల యొక్క వినియోగదారుల సూచీ పట్టిక ఆధారంగా (CPIAL's), ఏప్రిల్, 2019 తేదీ ప్రకారం సవరించబడినవి.